

Title: Need to launch a nationwide campaign for production and use of Ethanol and Bio-diesel as alternative fuels.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, देशभर के सामने ईंधन की कमी का विषय बार बार आ रहा है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। पिछली सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे, जिसमें इथानोल को शुरू में 5 प्रतिशत पेट्रोल में मिलाये जाने और बाद में इसे 10 प्रतिशत किये जाने का निर्णय किया गया था। इसके अलावा रतनजोत को खेती के माध्यम से बायो-डीजल की पैदावार देश में बढ़ाई जायेगी। जो पेट्रोल में शुरुआत की गई है, वह इस बात का आभास करते हुये कि निकट भविष्य में तेल के भंडार समाप्त हो जायेंगे। इसके अलावा समुद्र तल से कार्बन गैस हाइड्रेंट का दोहन करके वैकल्पिक रूप से लाभ उठाया जायेगा, इस प्रकार से रिकॉर्ड समय में इसकी स्टडी होकर योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका प्रयोग लोकोमोटिव, बी.ई.एस.टी. मुम्बई आदि में किया जा रहा है। प्लानिंग कमिशन का 1430 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव सामने आया है लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, ऐसी बात जानकारी में आई है कि शीरे से जुड़े हुये उद्योगों की जो लॉबी है या ऑयल टैंकर्स इम्पोर्ट करने वाली लॉबी है, उनके दबाव से यह कार्यक्रम स्थितिल किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये और हमारा तेल इम्पोर्ट जो प्रतिवर्ष 70-75 हजार करोड़ का हो रहा है, को देखते हुये इन वैकल्पिक ईंधन के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ायें और राष्ट्र हित में जो कार्यक्रम पिछली सरकार ने शुरू किये थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाये।